TP

Samyak
An Institute For Civil Services

RAS - 23 MAINS TEST SERIES

सिद्धि-II - 009

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 200**

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राज्य राजनीति, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले
Indian Political System, World Politics and Current Affairs

Paper - III (Unit - I)

Name :		**MARKS**	
Enroll. No.:	**Part**	**Attempted Questions**	**Marks Obtained**
Date of Birth :	**Part - A**	25	20.25
Medium : Hindi	**Part - B**	15	42.5
E-mail :	**Part - C**	07	33.5
Exam Date :	**Total**	47	102.25
Inviligator's Signature :			
ECN: **RCN:**	**Hindi:** 6.5	**English:** 0	

अनुदेश (Instructions)

1. परीक्षा शुरू होने से पहले पुस्तिका को जाँच लें।
   Please check the booklet before commencement of the exam.
2. अंक योजना प्रत्येक खंड के प्रारम्भ में दी गई है।
   The marking scheme is given at the start of every section.
3. अभ्यर्थियों को उत्तर निर्धारित शब्द सीमा से अधिक नहीं लिखना चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर अंक काटे जा सकते हैं।
   Candidates should not write more than the prescribed word limit in answers, violating this may result in deduction of marks.
4. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखें। बॉर्डर लाईन से बाहर प्रत्युत्तर नहीं लिखें। बॉर्डर लाईन के बाहर लिखे गये उत्तर को जाँचा नहीं जायेगा।
   Candidates are directed to write answers only in the prescribed space of booklet. They should not write answer outside the border line. Answer written outside the border line will not be checked.

	REVIEW PARAMETERS	SCALE			
		Good	Above Average	Average	Below Average
1.	**DOES THE ANSWER ADDRESS THE DEMAND OF THE QUESTION?**				
a.	**Answer Relevancy**		✓		
b.	**Answer Enrichment** points like use of: · **Key Terms/** Subject Vocabulary. Use of Commission/ report/ government publication/ judgements, etc. **Association with the Current Affairs** and use of examples to explain the concept and idea		✓		
2.	**HOW WELL IS THE ANSWER PRESENTED?**				
a.	**Structure** - Intro, Body, Conclusion		✓		
b.	**Presentation** – Using Subheadings/ points/ highlighting/ flowcharts/ diagrams/ maps		✓		
c.	**Language & Grammar**				✓
d.	**Word limit**			✓	

Detailed Comments / Feedback / Suggestions for Improvement
विस्तृत टिप्पणियाँ/फीडबैक/सुधार के लिए सुझाव

1.

① ज्ञान व अध्ययन सामग्री का स्तर अच्छा है, इसे निरन्तर बनाते हुए उत्तर लेखन हेतु प्रयासरत रहें।

② प्रस्तुतीकरण भी अच्छा है, बेहतरी हेतु Diagram व फ्लोचार्ट व महत्वपूर्ण Points को Highlight कर सकते हैं।

→ Content का निरन्तर Revision करते रहें।

→ कई प्रश्नों के उत्तर सराहनीय प्रयास है; इसे निरन्तर बनाए रखते हुए सकारात्मक रूप से अध्ययन करें। :)

→ हिन्दी में पत्र प्रारूप को भी आवश्यक रूप से पूर्णतः Attempt करने का प्रयास करें व English के Part को भी Attempt करें।

Keep it up...!

Part - A

Note : Answer the following questions in 15 words. Each question carries 2 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में गठित समितियों का नाम उल्लेखित कीजिये।
Mention the names of the committees formed in the context of local self-government in Rajasthan.

1) बलवंत राय मेहता समिति - 1957 → त्रिस्तरीय पंचायतीराज्य व्यवस्था
2) अशोक मेहता समिति - 1977 - द्विस्तरीय पंचायतीराज्य
3) P K थुंगन समिति
4)

भारत सरकार द्वारा गठित, ये राजस्थान के सन्दर्भ में नहीं। → गिरधारी लाल व्यास समिति
राजस्थान → हरीशचन्द्र माथुर समिति
– सादिक अली समिति
– कटारिया समिति

0.25

(Write above this line only)

2. 'नागरिक समाज' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Civil Society'.

सशक्त, शिक्षित जागरूक नागरिकों का समूह जो नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों तथा पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के लिए अपनी बात माँग व आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते हैं। यह दबाव समूह के रूप में कार्य।
उदा॰ मजदूर किसान संगठन द्वारा सूचना के अधिकार की माँग

राज्य से स्वतंत्र या गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन जो सामूहिक कल्याण की भावना से सरकार से अलग क्रिया।

1

(Write above this line only)

3. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों/अध्यक्षों को पद से मुक्त किये जाने के आधार बताइये।
Explain the grounds for disqualification of the members/chairmen of the Union Public Service Commission from their posts.

1) साबित कदाचार या असमर्थता
2) पद का दुरुपयोग, नैतिक अधमता का दोषी
3) संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण कर लिया हो
4) सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित
5) चित विकृत, मानसिक विकृत घोषित किया गया हो।

राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है

2

(Write above this line only)

4. राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए सम्पन्न चुनावों में विजयी सीटों की दलवार स्थिति को लिखिए।
Write the party-wise position of winning seats in the elections held for the 16th Assembly of Rajasthan.

सबसे बडा दल - भारतीय जनता पार्टी = 115 सीट
कांग्रेस = 70
भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) = 3 सीट
शेष रा.लो.पा → 1 सीट
राष्ट्रीय लोक दल → 1 सीट बहुजन समाज पार्टी → 2 सीट
निर्दलीय → 8 सीट

(Write above this line only)

5. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'पब्लिक ट्रस्ट' का सिद्धान्त।
The principle of 'Public Trust' propounded by the Supreme Court.

प्राकृतिक संसाधनों की न्यासधारिता के सिद्धांत से प्रेरित अवधारणा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संपत्ति की स्वामी ना होकर संरक्षक है जनता में इस संपत्ति का एक समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
→ प्राकृतिक संसाधनों के सन्दर्भ में अतः प्राकृतिक संरक्षण व न्याय की जिम्मेदारी सरकार की।
(1997 के मामले में निर्णय)

(Write above this line only)

6. संविधान के 'अनुच्छेद-231' पर टिप्पणी लिखिए।
Comment on 'Article 231' of the Constitution.

224 (231)

इसमे सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction)
1) केन्द्र व राज्यों के मध्य विवादों की सुनवाई
2) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों की सुनवाई
3) दो राज्यों के मध्य विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा।
(0)

(Write above this line only)

→ अनु. 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख।

7. 'डी-हाईफनेशन नीति' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'De-hyphenation policy'.

भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अपनाई गई नीति जिसमें भारत प्रत्येक देश के साथ स्वतंत्र नीति को अपनाता है, यह दूसरे देश के साथ रिश्ते से अप्रभावित रहती है।
उदा० इजराइल-फिलिस्तीन के साथ प्रयोग, फिलिस्तीन के साथ संबंध स्थापित करते हुए इजराइल के हितों को प्राथमिकता।

प्रतिकूल सम्बन्धों वाले देशों के साथ अलग, स्वतंत्र नीति

2

(Write above this line only)

8. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'अनुच्छेद-44'
'Article 44', was recently seen in the news.

ऐसा एकल कानून जो भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों में समान रूप से लागू है

राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग-4 में वर्णित प्रावधान :- राज्य एक समान नागरिक संहिता (UCC) हेतु प्रयास करेगा।
हाल ही में उत्तराखण्ड राज्य UCC लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है।
→ केन्द्र सरकार द्वारा भी UCC पर मसौदा नीति जारी।

गोवा प्रथम राज्य

1

(Write above this line only)

9. 'भारत का राज्यक्षेत्र', 'भारत संघ' से बड़ी अवधारणा है। कैसे?
'Territory of India' is a bigger concept than 'Union of India'. How?

भारत राज्यों का संघ है जिसमें विभिन्न राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश शामिल है जबकि भारत का राज्य क्षेत्र संघ से बड़ी अवधारणा है जिसमे भारतीय समुद्री सीमा 200 km की दूरी (EEZ), निर्जन द्वीप, भारतीय सैन्य बेस, अंटार्कटिक पर स्थित भारतीय केन्द्र शामिल है। Good

2

(Write above this line only)

वह भू भाग भी जहाँ भारत की सम्प्रभुता का विस्तार है

10. प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द 'समानता' पर टिप्पणी लिखिए।
Comment on the word 'Equality' mentioned in the Preamble.

विशेषाधिकार विहीन समाज

अर्थ :-
समानता से तात्पर्य सभी के साथ एक समान व्यवहार, धर्म, मूलवंश, जाति जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात कही गई है।
प्रावधान
⇒ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है।

1½

(Write above this line only)

11. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के सन्दर्भ में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को लिखिए।
Write the directive principles mentioned in the context of promotion of peace and security at the international level.

अनु० 51 में नीति निदेशक तत्व (भाग-4) में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य बताए हैं
1) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा।
2) सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मित्रवत संबंध
3) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से समाधान 4) अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों संस्थाओं का पालन।

Good

2

(Write above this line only)

12. 'ग्लोबल गेटवे' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Global Gateway'.

यह विश्व की उदार अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें व्यापार को संरक्षणवादी नीतियों का त्याग कर टैरिफ दर, आयात शुल्क में कटौती करते हुए "फ्री ट्रेड" को बढ़ावा शामिल है।
विभिन्न देशों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा।

0

यूरोपीय यूनियन द्वारा चीन की BRI के प्रत्युत्तर में सार्वजनिक व निजी निवेश हेतु अवसंरचना योजना।

(Write above this line only)

13. राजनीतिक अवसरवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of political opportunism.

राजनीति सिद्धान्तों की अवहेलना कर राजनैतिक स्वार्थों की सर्वोपरि रखना

राजनीति गतिशील अवधारणा है जिसमें बहुमत पाने व सरकार में शामिल होने के लिए समय व परिस्थिति के अनुरूप अपनी विचारधारा, नीतियों से समझौता, तात्कालिक लाभ के लिए (उदा० अकालीदल-भाजपा) गठबंधन, जम्मू कश्मीर मे PDP व BJP गठबंधन, बिहार मे JDU-BJP गठबंधन, महाराष्ट्र में शिवसेना तथा विभिन्न राजनीतिक विचारधारा - INDIA अलायंस) कांग्रेस, NCP

1 1/2

(Write above this line only)

14. 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Procedure established by law'.

जापान ?

अवधारणा - ब्रिटेन, संसदीय सर्वोच्चता का प्रतीक, विधि कितनी ही अतार्किक, असंगत क्यों ना हो अगर सही प्रक्रिया का पालन किया गया है तो विधि का अक्षरशः पालन किया जाता है। यह विधि के न्यायिक पुनरवलोकन को रोकता है मेनका गांधी वाद-1978 मे इसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत → विधि की सम्यक प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया।

2

(Write above this line only)

15. भारतीय सन्दर्भ में 'पंथनिरपेक्षता' का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए।
Explain the meaning of 'Secularism' in the Indian context.

भारतीय संदर्भ में तात्पर्य है - राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। भारत में धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया गया है → सर्वधर्म समभाव नीति पाश्चिम में धर्म का राजनीति से पूर्णतः पृथक्करण, 42वे संवि. संशो. 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल।

Good

2

(Write above this line only)

प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म को मानने हेतु स्वतंत्र।

16. विधानसभा व विधानपरिषद के मध्य किसी विधेयक को लेकर उत्पन्न होने वाले गतिरोध के कारणों को उल्लेखित कीजिए।
Mention the reasons for the deadlock arising between the Legislative Assembly and the Legislative Council regarding a bill.

1) जब किसी विधेयक पर व्यापक चर्चा नहीं हुई हो, जल्दबाजी में पारित।
2) शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत के विपरित हो?
3) जब सदस्य विधेयक पर एकराय न हो, जनता द्वारा प्रदर्शन
यद्यपि विधानपरिषद् को सीमित शक्तियाँ है, केवल एक बार विधानसभा को
जब विधानपरिषद् विधेयक को अस्वीकार करके पुनर्विचार के लिए भेजना
3 माह विधानपरिषद् अपने आपास रोक ले व कोई संशोधन कर।
ऐसा संशोधन जिससे विधानसभा सहमत नहीं।

(Write above this line only)

17. संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित पदाधिकारियों के पद उल्लेखित कीजिए।
Mention the posts of the officials mentioned in the Third Schedule of the Constitution.

तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान
1) प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद् 2) मुख्यमंत्री व मंत्रीपरिषद्
3) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश 4) हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्याया०
5) निर्यंत्रक, महालेखा परीक्षक (CAG) 6) महान्यायवादी 7) UPSC व अन्य आयोगों के
संसद व राज्य विधानमंडल अध्यक्ष व सदस्य

(Write above this line only)

18. संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में उल्लेखित किन्हीं चार विषयों का उल्लेख कीजिए।
Mention any four subjects mentioned in the context of local self-government mentioned in the 12th Schedule of the Constitution.

74 वा संवि० संशो० 1993 द्वारा भाग 9(A) में जोडी गई, कुल
18 विषय जोडे गए।
1) नगरीय स्वशासन व प्रशासन 3) मेलों, उत्सवों, हाट का आयोजन
2) स्थानीय कर 4) पेयजल व स्वच्छता।

(Write above this line only)

19. 'संसदीय सचिव' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Parliamentary Secretary'.

इस पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। मंत्री का जैसा दर्जा प्राप्त होता है। मंत्री नहीं होते हैं।
इस पर लाभ के पद के संबंध में विवाद है।
इसकी नियुक्ति - मुख्यमंत्री द्वारा व केन्द्र में प्रधानमंत्री द्वारा भी।
कार्य:- संसदीय कार्यों में विधानसभा अध्यक्ष की सहायता / वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता भी।

1½

(Write above this line only)

20. नगरपालिका एवं नगर परिषद की किन्ही तीन विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
Mention any three legislative powers of Municipality (Municipal Corporation) and City Council (Municipal Council).

नगरपालिका	नगर परिषद
1) प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक प्रावधान	1) प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक
2) गठन: 20,000 - 1 लाख जनसंख्या पर	गठन 1 लाख से अधिक जनसंख्या
3) न्यूनतम वार्ड - 13	2) अध्यक्षता - सभापति द्वारा
4) बैठक की अध्यक्षता - चेयरमेन	

संरचना नहीं, शक्तियों का उल्लेख करना है।
- आवासीय निर्माण & उपायों को विनियमित करना
- लाइसेंस जारी करना
- सफाई & उपरी etc

0

(Write above this line only)

21. संविधानवाद
Constitutionalism

संविधानवाद से तात्पर्य - "सीमित सरकार" अर्थात संविधान के विधि प्रावधानों के अनुरूप शासन संचालन, निरंकुश शासन का अभाव।
जिसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।
उदाहरण: → भारत संविधानवाद

1

(Write above this line only)

22. अभिलेख न्यायालय
Court of Record

अनु० 129 :- सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा
अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न वादों में लिए गए निर्णय
अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नजीर (आदर्श) होंगे। इन
निर्णयों को अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा। अन्य न्यायालयों के निर्णयों के सन्दर्भ में प्रयोग
इसकी अवमानना हेतु दण्ड देने का भी अधिकार

(Write above this line only)

23. विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विदेशों से धनप्रेषण प्राप्ति वाले चार शीर्ष राष्ट्रों के नाम लिखिए।
According to the report released by the World Bank, name the top four countries receiving remittances from foreign countries in the year 2023.

1) भारत I
2) बांग्लादेश मैक्सिको II
3) पाकिस्तान चीन III
4) नेपाल फिलीपीन्स IV

1/2

(Write above this line only)

24. 'खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023'
'Khelo India Para Games-2023'

पहली बार दिल्ली में आयोजन। खेलो इंडिया की नवीन पहल।
कुल 07 खेल शामिल → पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन,
पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा हॉकी आदि। टेबल टेनिस व वेटलिफ्टिंग

1/2

→ हरियाणा 105 पदक के साथ I स्थान।
→ 10-17 Dec
→ राजस्थान 6 वां स्थान (43)

(Write above this line only)

25. जलवायु परिवर्तन सूचकांक-2024 में शीर्षतम व निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीनं राष्ट्रों के नाम लिखिए।
Write the names of the three countries that have secured the top most and lowest positions in the Climate Change Index-2024.

शीर्ष
1. स्वीडन
2. नार्वे
3. फिनलैण्ड

शीर्ष
4 → डेनमार्क
5 → एस्टोनिया
6 → फिलीपीन्स

निम्नतम
67 → सऊदी अरब
ईरान
UAE

0

(Write above this line only)

Part - B

Note : Answer the following questions in 50 words. Each question carries 5 marks.
नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

1. मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है तथा उत्तरदायित्व के इस पक्ष में निहित अर्थों को समझाइये।
To whom is the collective responsibility of the Council of Ministers and explain the meanings inherent in this aspect of responsibility.

अनु० 75(2) : मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

चूंकि लोकसभा जनता का सदन है तथा सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा ही चुने जाते है अतः उत्तरदायित्व भी जनता के सदन (लोकसभा) के प्रति ही है। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी एक मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि मंत्रीपरिषद सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय लेती है तथा मंत्रीपरिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह है। उत्तरदायित्व के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद बर्खास्त किया जा सकता है → सरकार का विघटन।

प्रत्येक सदस्य निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है

3.5 Good

(Write above this line only)

2. सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार को उल्लेखित कीजिए।
Mention the original jurisdiction of the Supreme Court.

मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है - वे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जा सकती है : ये ! →

1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई।
2) संघ का किसी राज्य अथवा राज्यों के साथ विवाद की सुनवाई
3) विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों की सुनवाई
4) वे वाद जिनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हो
5) संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा → न्यायिक पुनरवलोकन
6) संघ सूची के विषयों पर उत्पन्न वाद :- विदेशी व्यापार, वाणिज्य

(Write above this line only)

3. "राजस्थान में आजादी के बाद जातियों के राजनीतिकरण का स्वरूप बदल रहा है।" स्पष्ट कीजिए।
"The nature of politicization of castes is changing after independence in Rajasthan." Explain.

राजस्थान में आजादी के बाद से ही राजस्थान की राजनीति जाट बनाम राजपूत राजनीति हावी रही है। प्रथम विधानसभा में जाट समुदाय द्वारा कांग्रेस तथा राजपूतों द्वारा राम राज्य पार्टी को समर्थन परंतु में कालान्तर में मण्डल आयोग के पश्चात शुरू हुई मण्डल v/s कमण्डल राजनीति ने SC, ST OBC व जनरल कैटगरी आधारित व्यवस्था को जन्म दिया जिससे वर्ग आधारित जातिगत समूहों का निर्माण हुआ। जातिगत जनगणना की मांग ने भी इस आधार को बल दिया है यही कारण है कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रमुख पदों के सीट वितरण में इन वर्गों को महत्व देना होता है। 16वी विधानसभा मे ट्रेंड → पूर्वी राजस्थान मे ST समुदाय, दक्षिणी राज० में SC समुदाय, तथा शेष राज० मे जनसंख्या के अनुरूप OBC में सभी को प्राथमिकता।

(Write above this line only)

4. वर्तमान में रूस-चीन के मध्य मजबूत होते सामरिक रिश्ते भारत के लिए किस प्रकार से चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं?
How can the currently strengthening strategic relations between Russia and China present challenges for India?

रूस-चीन के मध्य मजबूत रिश्तों ने भारत के लिए भू राजनीतिक चुनौती पेश की है
1) भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक है तथा हथियार से संबंधित तकनीक साझा करते है → चीन द्वारा इसे संतुलित करने का प्रयास भारत के लिए असुरक्षा।
2) ब्रह्मोस मिसाइल भारत-रूस की संयुक्त परियोजना है इससे भारत को रूस द्वारा चीन को गोपनीय जानकारी व तकनीक हस्तांतरण का भय है।
3) भारत द्वारा रूस को प्रमुख खाद्यान्न निर्यात किए जाते है तथा सस्ता व्यापार की स्थिति प्रभावित होगी।
4) भारत द्वारा क्रूड ऑयल का आयात रुपये में किया जा रहा है जिससे प्रभावित होने का डर।
5) चीन "BRI" को पूर्ति संतुलित करने के लिए भारत द्वारा उत्तर-दक्षिण गलियारे का प्रस्ताव किया गया है जिससे प्रभावित होने का डर।

(Write above this line only)

5. मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए।
Explain the relationships between Fundamental Rights and Directive Principles.

मौलिक अधिकार (भाग-3) तथा भाग-4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार जहाँ राजनैतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते है तथा नागरिकों के सर्वांगिण विकास के लिए आवश्यक है वहीं नीति निदेशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते है, ये राज्य को नीति निर्माण के संबंध में दिए गए निर्देश है जिसके पालन से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है।
दोनों में से किसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए यह हमेशा विवादित रहा है। 1990 के SR बोम्मई वाद में स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DPSP तथा FR's एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है अपितु पूरक है दोनो का उद्देश्य लोगों का कल्याण है। फिर भी दोनों के मध्य विवाद होने पर FR's को DPSP पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

(Write above this line only)

6. ''भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण है।'' उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।
"The Indian Constitution is a combination of rigidity and flexibility." Explain the above statement.

BR अम्बेडकर के अनुसार- भारतीय संविधान समय व परिस्थिति के अनुरूप संघात्मक अथवा एकल या कठोर अथवा लचीला हो सकता है। इसके प्रावधान:-
कठोर संविधान:- संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत तथा संघात्मक मामलों में आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। केन्द्र व राज्य के मध्य विवादों पर न्यायपालिका द्वारा निर्णय, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
लचीला संविधान:- 1) कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन (राज्य के नाम, सीमा, नए राज्य का निर्माण), राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण। अत: भारतीय संविधान में कठोर व लचीले का समन्वय है

(Write above this line only)

7. "विधानसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है न कि विधानपरिषद।" स्पष्ट कीजिए।
"The Legislative Assembly is the real representation of the people and not the Legislative Council." Explain.

संविधान के भाग-6 में राज्य की विधायिका व कार्यपालिका वर्णन है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा फर्स्ट फास्ट द पोस्ट आधार पर होता है जबकि विधानपरिषद के सदस्यों में 1/6 सदस्य मनोनीत व शेष सदस्य (विधानसभा) सदस्य, ग्रेजुएट, स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, इनके चुनाव में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। अत: 'विधानसभा' जनता का सदन है जो आम जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है जबकि विधानपरिषद प्रबुद्ध जनों का सदन है जो विधि निर्माण में विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है। अत: जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण ही विधानसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है

(Write above this line only)

8. "विधानसभा की बैठक का स्थगन विधानसभा के सत्रावसान की तुलना में सीमित क्षेत्र/प्रक्रिया रखता है।" उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।
"Adjournment of the meeting of the Legislative Assembly has limited scope/procedure as compared to prorogation of the Legislative Assembly." Explain the above statement.

स्थगन :- जब विधानसभा सत्र की बैठक के दौरान किसी विधेयक पर आम सहमति ना बने, लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा के दौरान उत्पन्न विवाद, अशोभनीय भाषा का प्रयोग आदि के कारण जब विवाद हो तथा बैठक जारी न रखा जा सके तो विधानसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है किंतु वक्त के लिए स्थगित करेगा, पुनः संचालन कब होगा ये सब अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है इस हेतु निश्चित प्रक्रिया का अभाव है। सत्रावसान राज्यपाल द्वारा सत्र समाप्ति की घोषणा की जा सकती है इस हेतु संविधान में निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। दो सत्रों के मध्य 6 महिने से अधिक अंतर नहीं हो सकता है परंतु कोई सत्र कब समाप्त करना है व आहूत करना है इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है।

(Write above this line only)

9. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रचलित 'कॉलेजियम प्रणाली' के उद्भव/विकास पर टिप्पणी लिखिए।
Write comment on the origin/development of the 'Collegium System' prevalent in the context of appointment of judges of the higher judiciary.

प्रारंभ में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती थी जिसमें प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्याया० के मुख्य न्यायाधीश सदस्य। इसे 1st Judges case में चुनौती दी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कालेजियम व्यवस्था को लागू किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य दो न्यायाधीश होते है थे। 2nd Judges case में सुप्रीम कोर्ट ने कालेजियम प्रणाली का विस्तार किया इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश (3) व एक संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सदस्य द्वारा नियुक्ति का प्रावधान

(Write above this line only)

10. प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी है, में उल्लेखित लक्ष्यों/उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the goals/objectives mentioned in the Preamble which is the key to the Constitution.

K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है जिसमे प्रमुख उद्देश्य:

1) भारत का स्वरूप - स्वतंत्र संप्रभु लोकतंत्रात्मक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणराज्य के आदर्शों को बनाए रखना।

2) लक्ष्य: सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसरों की समानता की प्राप्ति।

व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली

3) राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बढ़ाने वाली बंधुता को प्रोत्साहित करना।

अत: प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है।

Good

स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों का वर्णन

3

(Write above this line only)

11. "भारत में संसदीय नियंत्रण वास्तविक की बजाय सैद्धान्तिक है।" उक्त कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
"Parliamentary control in India is theoretical rather than practical." Present arguments in favor of the above statement.

1) भारत में संसदीय नियंत्रण मुख्यत: संसदीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिसमें सत्ता प्राप्त दल के सदस्यों का बहुमत होता है।

2) संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका ही विधायिका का सदस्य होती है अत: नियंत्रण प्रभावी नहीं हो पाता है।

3) सत्ताधारी दल का अपार बहुमत संसदीय नियंत्रण को कमजोर करता है

4) व्हीप जारी किए जाते हैं जिससे संसदीय सदस्य आत्मचेतना से सरकार के विरुद्ध वक्तव्य नहीं दे पाते हैं

विपक्ष का अभाव

सैद्धान्तिक → संसद का विशेष आकार, समयाभाव, विशेषज्ञता का अभाव, अध्यादेश, गिलोटिन का प्रयोग

2

संसद में स्थिर व सशक्त विपक्ष का अभाव

(Write above this line only)

12. संविधान के अनुच्छेद-72 में उल्लेखित राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों पर टिप्पणी कीजिए।
Comment on the pardoning powers of the President mentioned in Article 72 of the Constitution.

पांच प्रकार की शक्तियाँ हैं –

1) क्षमादान :- संघ/राज्य सूची के विषय पर मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति को पूर्ण क्षमा सैन्य न्यायालय के निर्णय पर भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।

2) लघुकरण :- सजा की प्रकृति बदलते हुए सजा कम करना, मृत्युदण्ड → आजीवन कारावास

3) परिहार :- प्रकृति नहीं बदलती लेकिन सजा कम हो जाती है 2 वर्ष → 1 वर्ष कठोर कारावास

4) प्रविलम्ब :- मृत्युदण्ड की सजा पर अस्थायी रोक। अपील का अवसर प्रदान करती है।

5) विराम :- विशेष दशा में सजा कम की जा सकती है। उदा० → गर्भवती स्त्री के मृत्युदण्ड की दशा में। → केहर सिंह प्रकरण / निस्तार जारी रखें

good 5

(Write above this line only)

13. 'स्वतंत्रता के अधिकार' के अन्तर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकार व उन पर आरोपित युक्तियुक्त प्रतिबंधों को उल्लेखित कीजिए।
Mention the fundamental rights mentioned under 'Right to Freedom' and the reasonable restrictions imposed on them.

स्वतंत्रताएं ही हैं।

अनु० 19(1) में 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। 19(1)(a) → विचार व अभिव्यक्ति (b) शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन (c) संघ बनाने (d) स्वतंत्र विचरण → भारत के राज्य क्षेत्र में (e) निवास की स्वतंत्रता (g) आजीविका की स्वतंत्रता

प्रतिबंध

19(2) :- 19(1)(a) पर प्रतिबंध के 8 आधार 1) भारत की एकता व अखण्डता 2) सुरक्षा 3) विदेशी संबंध 4) न्यायालय की अवमानना 5) मानहानि 6) लोक व्यवस्था 7) नैतिकता 8) अपराध उद्दीपन

19(3) :- 19(1)(b) पर → 1) लोक व्यवस्था 2) एकता व अखण्डता

19(4) :- 19(1)(c) पर → 1) लोक व्यवस्था 2) एकता व अखण्डता 3) नैतिकता

19(5) 19(1)(d) व (e) पर → 1) जनजातीय लोगों के हित में 2) लोक व्यवस्था

19(6) 19(1)(g) पर → लोगों के हित में → लाइसेंस अनिवार्य किया जा सकता है।

5 good
पर्याप्त व सटीक तथ्य

(Write above this line only)

14. मंत्रिमण्डल व मंत्रिपरिषद् में मूलभूत अन्तर लिखिए।

Write the basic differences between Cabinet and Council of Ministers.

मंत्रिमण्डल		मंत्रिपरिषद्
1) अनु० 356 में उल्लेख (352 में)	-	अनु० 74 में (75 में)
2) छोटा होता है (लघु निकाय) (शब्द का)	-	बड़ा होता है
3) संख्या निर्धारित नहीं (उल्लेख)	-	विधानसभा/L.S की सीटों का 15%
4) महत्वपूर्ण निर्णय लेता है		सामान्य निर्णय लेता है। (मंत्रिमण्डल के निर्णयों को लागू करता)
5) सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं		सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा या लोकसभा के प्रति
6) केवल कैबिनेट मंत्री शामिल		कैबिनेट, राज्यमंत्री, उपमंत्री (तीन श्रेणियाँ)

— वास्तविक शक्तियाँ
निहित
— मंत्रिपरिषद् को निर्देश

2½

(Write above this line only)

15. वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों द्वारा पश्चिम एशिया व उत्तरी अमेरिकी देशों में सामना की जाने वाली चुनौतियों को लिखिए।

Write the challenges currently faced by Indian diaspora at the global level in West Asia and North American countries.

(Write above this line only)

16. वर्तमान में भारत-भूटान के मध्य संबंधों में विद्यमान चुनौतियों को लिखिए।
Write the challenges existing currently in the relations between India and Bhutan.

संक्षिप्त भूमिका बनाते हुए उत्तर शुरू करें।

चुनौतियाँ :-

1) चीन के विस्तारवाद से उत्पन्न चुनौतियाँ :- डोकलाम → भूटान-चीन व भारत के मध्य स्थित आवश्यक क्षेत्र

2) निवेश संबंधी → जल विद्युत परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सम्बन्धी विवाद।

3) भूटान सरकार के चीन के प्रति बदलता दृष्टिकोण → हालकी चीन यात्रा जिसमें विभिन्न समझौते। भूटान के विदेश मंत्री का

4) 2008 से भूटान स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है जिनसे भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। भूटान अपनी जलमार्ग निर्भरता बांग्लादेश की तरफ स्थानान्तरित करने के कारण अविश्वास

5) सैन्य प्रशिक्षण, जल-बंटवारा, व्यापार व आधिशेष

6) चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति, डेब्ट ट्रैप नीति।
→ BBIN पहल का भूटान के समर्थन में विरोध है।

2

(Write above this line only)

Part - C

Note : Answer the following questions in 100 words. Each question carries 10 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. राज्यपाल का पद संवैधानिक होते हुए भी नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण कमतर आंका जाता है, इस सन्दर्भ में राज्यपाल के निर्वाचन के पक्ष व विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
Despite being constitutional, the post of Governor is undermined due to the appointment process. In this context, give arguments in favor and against the election of the Governor.

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को अनेक स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है जिस कारण इसका प्रमुख अधिक महत्वपूर्ण है। संघीय शासन व्यवस्था में यह केन्द्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। सरोजिनी नायडु द्वारा इस पद की तुलना 'तोते' से तथा पट्टाभि सीतारमैया ने "अभिवादन स्वीकार करने वाला" से की है।

निर्वाचन के पक्ष में:	विपक्ष में
1. राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है तो राज्यपाल का क्यों नहीं। (केन्द्र द्वारा नियुक्ति से संघीय व्यवस्था की अवहेलना)	1) संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख अत: आवश्यक नहीं
2) निर्वाचन से उत्तरदायित्व में वृद्धि व जनकांक्षाओं की पूर्ति का नैतिक दबाव,	2) निर्वाचन से मुख्यमंत्री व राज्यपाल में हितों का टकराव। (अत: निर्वाचन नहीं होना चाहिए, केवल संवैधानिक प्रमुख मत)
3) निर्वाचन से प्रतिष्ठा में वृद्धि, जनहित में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। (केन्द्र द्वारा नियुक्ति होने पर राज्य के जो...)	3) समय व धन का अपव्यय
4) निर्वाचन से शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी में वृद्धि। (अभाव) (संघ व राज्य में अलग-अलग दल की सरकार होने पर टकराव नहीं होगा।)	4) सत्ता के दो केन्द्र स्थापित होंगे जिससे नीति निर्माण में अनिश्चितता व टकराव। निर्वाचित राज्यपाल पर केन्द्र का नियंत्रण मुश्किल

4

राज्यपाल संघात्मक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिस कारण यह राज्य में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाता है। (आरक्षित विधेयकों में कमी) यह संघ व राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता व

(Write above this line only)

2. राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना का लक्ष्य बताते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाओं तथा उनके शमन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लिखिए।

While explaining the aim of establishing the National Integration Council, write down the obstacles facing national integration and the steps to be taken to mitigate them.

राष्ट्रीय एकता परिषद :- क्षेत्रवाद, भाषावाद, नृजातियता व अन्य सांस्कृतिक भौगोलिक विविधताओं के आधार पर अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोककर एकता व अखण्डता सुनिश्चित करने हेतु स्थापित। संविधानेत्तर निकाय है।

1961 में सलाहकारी निकाय के रूप में

लक्ष्य
→ अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना।
→ राष्ट्रीय, एकता अखण्डता को बढ़ावा।
→ राज्यों के सामूहिक हितों पर चर्चा करना।

धर्मनिरपेक्षता, समानता, सभी समुदायों में बंधुत्व व साम्प्रदायिकता, जातिवाद आदि समस्याओं का समाधान

बाधाएं :- 1) क्षेत्रवाद : क्षेत्रवाद के नाम पर राज्यों की मांग → गोरखालैण्ड, हरित प्रदेश
2) नृजातियता :- नृजातियता के आधार पर अलगाव :- बोडोलैण्ड
3) भाषायी आंदोलन :- उत्तर बनाम दक्षिण हिन्दी विरोध आदि
4) वर्ग संघर्ष :- शोषक-शोषित समाज, सर्वहारा व मजदूर
5) नक्सलवाद 6) सीमापार आतंकवाद (कश्मीर)

धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, कुलवाद, गरीबी, राजनीतिक अवसरवादिता

उपाय :- विविधता का सम्मान किया जाए तथा पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए
2) संतुलित समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा → शोषक-शोषित भेद समाप्त
3) जनजातीय हितों की रक्षा → 'EJA' का इन क्षेत्रों में प्रभावी पालन।
4) अलगाववाद को रोकने हेतु : टेरर फंडिंग, हवाला की जांच, संस्थानों पर प्रतिबंध
5) भाषा का मुद्दा संवेदनशील है, मातृभाषा को बढ़ावा, हिन्दी को थोपने से बचा जाए
अतः भारतीय एकता अखण्डता की रक्षा हेतु समन्वित समावेशी प्रयास की आवश्यकता है।

बेरोजगारी, आर्थिक विषमता को दूर करने के समावेशी प्रयास, आर्थिक लाभों का न्यायपूर्ण वितरण, राजनीतिक वातावरण में सुधार, भ्रष्टाचार व जातिवाद का उन्मूलन etc

(Write above this line only)

3. नीति निदेशक तत्वों के आलोचनात्मक बिन्दुओं को लिखते हुए इनको लागू किये जाने के सन्दर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बताइये।

Critically analyse the points of the Directive Principles and tell the steps taken by the government regarding their implementation.

भाग-4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व " सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करते है। ये राज्य सरकार को निर्देश है जिनसे लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके।

आलोचना :- 1) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। K.T शाह - अतिरिक्त कर्म काण्ड

2) इनकी प्रकृति सकारात्मक है, राज्यों पर बाध्यता आरोपित नहीं करती।

3) ये केवल आदर्श रूप है यथार्थ में इनका पालन संभव नहीं है।

4) ये अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, राज्यों को दिए गए निर्देश मात्र है।

प्रयास :- (1) समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार के प्रयास

1) श्रम कानूनो का सरलीकरण :- Minimmum wages Act - 1948 equal remunivation Act 1976, श्रम संहिता 2020 का क्रियान्वयन

2) छूआछूत :- नागरिक अधिकार संरक्षण कानून - 1976 स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

3) निःशुल्क विधिक सहायता हेतु RLSA की स्थापना।

(2) गांधीवादी लक्ष्य :- 1) अनु 40 की पालना मे 73rd व 74th CAA - 1992

2) कुटीर उद्योग : जिला उद्योग संघ, हस्तशिल्प मंडल, MSME नीति लागू, GI टैग, ODOP व खादी को बढ़ावा। जैविक कृषि का उन्मूलन etc

3) अनु 43(b) → सहकारी संघ → सहकारिता मंत्रालय → सहकारी से समृद्धि स्थापित

(3) उदार - बौद्धिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु :- i) मातृत्व अवकाश का प्रावधान ii) RTE - 2009 iii) वन अधि० 1980 iv) पर्यावरण संरक्षण अधि० 1986 v) UCC हेतु प्रयास जारी

नीति निदेशक तत्व संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है जिन्हे प्राप्त करने हेतु राज्य प्रयत्नशील है।

(Write above this line only)

Good

4. "राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से व्यक्तियों के अधिकार व राज्यों की स्वायत्तता पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं।" उक्त कथन को स्पष्ट करें।

"The declaration of national emergency has far-reaching effects on the rights of individuals and the autonomy of states." Explain the above statement.

भाग 18 में 352-360 तक।

अनु० 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है आधार → 1) बाह्य आक्रमण 2) युद्ध 3) सशस्त्र विद्रोह (44CAA द्वारा)

358 :- राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनु० 19 में प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसमें 44CAA 1978 द्वारा संशोधन। 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर आपातकाल में समाप्त नहीं होंगे।

अनु. 359 :- राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। 44वां संवि-संशोधन :- इस दौरान अनु० 20 व 21 में प्रदत्त मूल अधिकार समाप्त नहीं।

व्यक्तियों पर प्रभाव
1) मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं
2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से राज्य निरंकुश हो सकता है।
3) नागरिक अधिकारों का हनन
4) लोकतंत्र को हानि

राज्य पर प्रभाव
1) राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति केन्द्र में निहित हो जाती है। → संघीय स्वरूप → एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है
2) राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण
3) विधायिका शक्तियों का ह्रास — वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित।
4) केन्द्र के निर्देशों के अनुरूप शासन संचालन

यद्यपि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संघात्मक ढांचे को नुकसान पहुंचता है व एकात्मक शक्तियों का प्रयोग संघ द्वारा किया जाता है परंतु ये राष्ट्रीय अखण्डता व एकता को बनाए रखने हेतु आवश्यक है बशर्ते इसका प्रयोग राजनैतिक पूर्वाग्रह या दुराग्रह से प्रेरित न हो।

राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है

(Write above this line only)

5. केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य टकराव/विवाद के बिन्दुओं पर लेख लिखते हुए टकराव/विवाद शमन के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

While writing about the points of conflict/dispute between the Central Government and the State Governments, present suggestions for mitigating the conflict/dispute.

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें राज्य संघ के अधीनस्थ ना होकर, समकक्ष व स्वायत्त है लेकिन फिर भी विभिन्न मामलों में इनके मध्य टकराव पैदा होता है जो निम्न है:

1) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह ना लिया जाना
2) राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती
3) अनु० 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग — सम. 200 व 201 का प्रयोग
4) केन्द्रीय जाँच एजेन्सियों (CBI, ED, NIA) का राजनैतिक प्रयोग
5) राज्यपाल द्वारा स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग — समवर्ती विषयों पर केन्द्र की प्राथमिकता
6) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तैनाती
7) केन्द्र व राज्यों के मध्य राजस्व वितरण, अनुदान व विशेष राज्य के दर्जे की माँग को लेकर टकराव। — good; जैसे जल संबंधी विवाद।

(राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता)

समाधान :- 1) सरकारिया आयोग व पूंछी आयोग की सिफारिशें लागू हो — 1983, 2007
2) सहकारी संघवाद को बढ़ावा हेतु नियमित समन्वय
3) अंतर्राज्यीय परिषद की नियमित बैठके आयोजित हो व इसकी सलाह बाध्यकारी हो। — सहकारी नीतियों का क्रियान्वयन
4) राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु मुख्यमंत्री सम्मेलनों का आयोजन — केन्द्र व राज्य की भूमिकाओं की स्पष्टता
5) क्षेत्रीय परिषदों, नीति आयोग की प्रभावशाली भूमिका — विवादित कानूनों व नीतियों में संशोधन
6) राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए जिससे आपसी विश्वास में वृद्धि व संघवाद संविधान का मूल ढांचा है अतः हितों के टकराव से बचने के प्रयास हो

(Write above this line)

6. निम्न बिन्दुओं पर लेख लिखिए/टिप्पणी कीजिए।/Write article/comment on the following points.

1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व इसके कारण उत्पन्न प्रभाव/International terrorism and its resulting effects

2. इजरायल-हमास संघर्ष की निरन्तरता के भारत व विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव/Impact of continuation of Israel-Hamas conflict on India and the world

(सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक)

जब आतंकवादियों द्वारा अपनी मांगो को मनवाने हेतु आमजन व सरकार को भयभीत करने के उद्देश्य से हिंसा, बमविस्फोट आदि हिंसक गतिविधि का प्रयोग किया जाता है तो इसे आतंकवाद कहते है यह एक वैश्विक समस्या है। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद वैश्विक आतंकवाद को मान्यता मिली व संयुक्त प्रयास प्रारम्भ हुए। भारत में 26/11 मुम्बई आतंकवादी हमला। 9/11 हमले के बाद अमेरिका द्वारा आपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया।

प्रभाव :- 1) मानवता को हानी, जान माल का नुकसान 2) ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित (विदेशी व्यापार व निवेश में प्रतिकूलता) 3) शरणार्थी संकट 4) मानवाधिकारों का हनन 5) स्त्रियों व बच्चों पर अत्याचार 6) आर्थिक विकास व संवृद्धि हतोत्साहित

विश्व के विभिन्न धार्मिक समूहों में अविश्वास व सौहार्द में कमी। → असुरक्षा व भय का वातावरण बनना

2) भारत पर प्रभाव

1) भारतीय प्रवासियों को नुकसान
2) निवेश पर नकारात्मक प्रभाव
3) भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर प्रभाव (पश्चिमी एशिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा का मुद्दा)
4) इजरायल द्वारा भारत में संचालित प्रोजेक्ट में विलम्ब
5) कृषि उपकरण व तकनीक (रक्षा उपकरण) महंगी हो सकती है

विश्व पर प्रभाव

1) ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित
2) हूती विद्रोहियों के समर्थन से मालवाहक जहाजों की हाईजैकिंग
3) धार्मिक कट्टरता से मध्य एशिया में धार्मिक युद्ध का खतरा (इस्लामिक जगत में विभाजन)
4) ग्लोबल एनर्जी संकट उत्पन्न
5) शस्त्रीकरण की होड़ (परमाणु युद्ध की आशंका)
6) वैश्विक व्यापार, शांति, स्थिरता पर संकट (इकोनॉमिक कॉरिडोर में बाधा; वैश्विक द्विध्रुवीयता का उभार सम्भव)

यूरोप के साथ नोवहन व्यापार में बाधा

2

7. निम्न बिन्दुओं पर लेख लिखिए/टिप्पणी कीजिए।/Write short article on the following points.

1. न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा व सीमाएँ/Concept and limitations of the judicial review

2. राज्यपाल को विषयान्तर्गत जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य/Duties of the Chief Minister regarding giving relevant information to the Governor

न्यायिक पुनरावलोकन :- न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। यह संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक है। आधार : अनु० 13, 14, 21, 32, 226 आदि
न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। यह सरकार के स्वच्छाचारी कार्यों को रोकता है तथा संविधानवाद की स्थापना करता है।

सीमाएँ :- 1) कोहिलोवाद मे स्पष्ट किया कि केवल 24 APR 1973 के बाद के कानून जो 9वी अनुसूची में जोडे गए उनकी समीक्षा की जा सकती है।
2) न्यायिक समीक्षा, न्यायिक आतंक में नही बदलनी चाहिए।
3) यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरित है।
4) उन्ही कानूनो की समीक्षा हो जिनमे संविधान की व्याख्या से संबधित प्रश्न हो

2) मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनु० 167 मे वर्णित
1) मुख्यमंत्री समय-समय पर प्रशासनिक व विधायी कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराएगा।
2) राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक व विधायी कार्यों की सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा।
3) ऐसा विधेयक जिसपर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिमण्डल ने नही तो उसको मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहेगा।
4) मंत्रिपरिषद की बैठको से संबधित लिए गए निर्णयो से राज्यपाल को अवगत कराएगा।

हिन्दी व्याकरण- पारिभाषिक शब्दावली व प्रारूप-लेखन-विज्ञप्ति

1. निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिन्दी पारिभाषिक शब्द लिखें? अंक- 10

(i) Ascertain – सुनिश्चित करना 1/2

(ii) Brokerage -

(iii) Conversion- रूपान्तरण

(iv) Inspection - निरीक्षण

(v) Memorandum - ~~अनुस्मारक~~ ज्ञापन

(vi) Negligence - ~~3~~ उपेक्षा

(vii) Ordinance - अध्यादेश

(viii) Respondent - प्रतिवादी

(ix) Statement - कथन / विवरण

(x) Unofficial - अकार्यालयी / अशासकीय 1/2

total 6

3. प्राचार्य, राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय बाँसवाड़ा की ओर से प्रायोगिक परीक्षाओं के स्थगन की विज्ञप्ति जारी कीजिए। अंक- 10

राजस्थान सरकार

कार्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँसवाड़ा

प०क्र० 39/रामबा/परीक्षा/89/2024 दिनांक : 09 अप्रैल 2024

विज्ञप्ति सूचना से

बी॰ए॰ प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ जोकि

दिनांक

½

Note→ प्रारूप को पुनः अवलोकर कर पूर्ण लिखने का प्रयास करें।

सम्यक (TM)
॥आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः॥

English Grammer – Phrsal Verbs and Idioms

(A) Rewrite choosing the appropriate expression to form a meaningful sentence (Q. No. 1-10) Marks : 10×1 = 10

1. The administration helped to *using out/bring about* a peaceful settlement.

2. I *came by/came across* my old friend in the market yesterday.

3. His income has been *falling back/falling off* for the last two years.

4. The cat *got round/through* the kitchen window.

5. He cannot *keep back/from* the use of tobacco.

6. Big powers try to *fish in troubled sea/fish in troubled waters* in the third world countries.

7. By his kindness today, he has *made amends/made amendments* for his past insolence.

8. All separatist tendencies must be *nodded in the bud/nipped in the bud.*

9. Some clerks in this office are in the habit of taking *French leave/English leave.*

10. This progressive company gives a *sphere deal/a square deal* to this employees.

(A) Rewrite choosing the appropriate expression to form a meaningful sentence (Q. No. 1-10) Marks : 10×1 = 10

1. India and Pakistan are *at daggers drawn/at sixes and sevens* these days.

2. Mohan *looked blank/looked blue* as he had failed.

3. The local M.L.A. *fell from grace/hung in balance* when he was arrested for smuggling.

4. Our village is flying into a rage/has taken a quantum leap in the field of education.

5. Neighbours should not quarrel and should bury the hatchet/hang fire.

6. He is *at a stone's throw/all at sea,* he does not know what to do.

7. The government's promise to make the pare teachers permanent is only *an eye wash/a black leg.*

8. The first prize in lottery proved *a sine die/a windfall* for him.

9. Our captain scored a century on his *maiden appearance/exparte.*

10. One who works by *ins and outs/fits and starts* can't succeed.

1990 1993

Samyak
An Institute For Civil Services

GET UPTO 100% SCHOLARSHIP

"CIVIL SERVICES DAY" पर सम्यक् प्रस्तुत कर रहा है

TOP 100 विद्यार्थियों को LBSNAA(मसूरी) का FREE TOUR

CIVIL SERVICES OLYMPIAD For RAS

1st PRIZE
BIKE
+
100% SCHOLARSHIP

2nd PRIZE
LAPTOP
+
90% SCHOLARSHIP

3rd-5th PRIZE
MOBILE
+
80% SCHOLARSHIP

NCERT नींव निर्माण COURSE ~~₹10000~~ FREE + MINIMUM 25% SCHOLARSHIP + RAS PRE & MAINS SOLVED PAPERS BOOKLET FREE TO ALL PARTICIPANTS

T&C APPLY

YOU CAN ALSO AVAIL SCHLOARSHIP @SAMYAKGURUKUL

परीक्षा की तिथि 21 APRIL | परीक्षा का समय 9:00 से 10:30 AM | रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹51 | FOR MORE INFO 9875170111